ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4 अद्भूत कृतियों के रचयिता देवशिल्पी विश्वकर्मा

रविवारीय 15-21 सितंबर 2019, संस्करण-1, अंक-6 | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

सूचना

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

जैविक खेती के लिये राशि देगी सरकार

रांची : जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की राशि देगी। यह राशि तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर पर दी जायेगी। झारखंड के सभी जिलों में 30 हजार हेक्टेयर की कृषि भूमि पर तीनवर्षीय जैविक खेती की योजना को लागू किया जायेगा।इस योजना से 30000 किसानों को लाभ होगा। वर्ष 2022 तक के लिये कैबिनेट ने 100 करोड़ की योजना के लिये स्वीकृति दी है।

ठेला और रेस्तरां वालो को लेना होगा प्रशिक्षण

रांची: राज्य भर के 40 हजार खाद्य व्यवसायियों को प्रशिक्षण लेना होगा। स्वास्थ्य सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने इसके आदेश दिये हैं। यह प्रशिक्षण खाने पीने की चीजों को साफ सफाई से तैयार करने, उसकी पैकिंग और सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से परोसने के लिये होगा। इसके लिये बेसिक कोर्स का 600 और एडवांस कोर्स का 800 रूपये का शुल्क लिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आवश्यक है। ठेला और वेंडर वाले खाद्य व्यवसायियों को एफएसएसएआई से निबंधन कराना आवश्यक है। प्रशिक्षण के बाद वेंडरों को ग्लब्स, नेपकीन एवं किताबें दी जायेंगी साथ ही दिये गये प्रमाणपत्र को अपने प्रतिष्ठान में शो करना होगा। प्रशिक्षण के लिये सात एजेंसियों का चयन किया गया है।

सामान्य लेकिन असमान रहा है मॉनसून

इस वर्ष मॉनसून अब तक सामान्य रहा है, लेकिन इसके असमान रहने से देश के कई हिस्से जहां अतिवृष्टि और बाढ से प्रभावित हैं वहीं कुछ हिस्से सूखे या कम बारिश के शिकार हुये हैं। देश के तकरीबन सभी बड़े डैम और झीलों में पानी प्रचुर मात्रा में एकत्र हुये हैं लेकिन झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक के कई हिस्से कम बारिश वाले रहे हैं। मध्यप्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो मॉनसून जाते जाते भी कहर बरपा रहा है। अब तक 800 मिमी से ज्यादा बारिश हो चुकी है और तालाबों, डैमों, झीलों में जो जल एकत्र हुआ है उससे अब अच्छे रबी के फसल की उम्मीद बढी है। रांची में मॉनसून के कमजोर रहने नदियों नालों के अतिक्रमित होने के कारण तीनों डैमों में पानी औसत से कम एकत्र हुआ है।

लाजवाब है झारखंड का नया विधानसभा भवन

रांची : झारखंड में नये विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथो हो गया। भवन बहुत ही भव्य है और निर्धारित समय में बन कर तैयार हुआ है। नये विस भवन को देख कर बरबस ही मुंह से ये कहावत निकल जाती है कि देर आये दुरूस्त आये। ये अफसोस की बात रही कि राज्य बनने के तकरीबन दो दशक पूरे होने को थे तब जाकर झारखंड को अपना विधानसभा भवन मिला। अब तक झारखंड विधानसभा का काम एचइसी के भवन में चल रहा था। भवन का कैंपस 39 एकड़ का है जो रांची के नगरी स्थित कूटे गांव में है। यह इमारत तीन मंजिली है और इसके निर्माण में 465 करोड़ रूपये खर्च हुये हैं। इसके निर्माण की नींव मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 12 जून 2015 को रखी थी। अब तक विधानसभा का कार्य एचइसी से लिये गये किराये के भवन में होता रहा।

भवन के उद्घाटन को भी यादगार बनाया गया , मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास

क्यों खास है झारखंड विधानसभा का यह भवन?

सिर्फ भव्यता के लिहाज से नये भवन को नहीं देखना चाहिये। इसमें कोई दोराय नहीं कि गुंबद लिये यह विशाल भवन बहुत खुबसूरत है। इसके अलावा देश का पहला ऐसा विधान सभा है जो पेपरलेस है।

57220 वर्ग मीटर में तीन मंजिले भवन का निर्माण हुआ है।

विधानसभा भवन के गुंबद की ऊंचाई 37 मीटर है

विधानसभा भवन में जल संचयन और ऊर्जा संरक्षण की व्यवस्था है

सौर ऊर्जा से विधानसभा भवन में होगी बिजली की आपूर्ति

सभी विधायकों के डेस्क में हीं सारे डिजिटल उपकरण, टैब लगे हुये हैं। यहां कागज की बर्बादी नहीं होगी। इंटरनेट से सारी सूचनायें तुरंत मिलेंगी।

ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लिया गया संकल्प

रांची: जेसीआई इंडिया का जेसीआई वीक के तहत उड़ान की सदस्यों ने आपस में मिलकर ज़ीरो वेस्ट पर चर्चा की, ये निर्णय लिया गया की पॉलीथीन मुक्त समाज का निर्माण कराना है। वातावरण कैसे शुद्ध रहे,वाटर हार्वेस्टींग,प्रदूषण से मुक्ति,पेपर बैग को बढ़ावा देना इत्यादि मुद्दों पर सदस्यों ने पहले ख़ुद अपनाने का संकल्प लिया,और कहा कि अपने संसाधन का दोहन होने तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने का जिम्मा भी हरेक नागरिक का है। इस कार्यक्रम के दौरान उड़ान की अध्यक्ष आभा भंडारी,सचीव अनीता अग्रवाल,वृंदा अग्रवाल,अर्चना मुरारका,राखी जैन सदस्य राखी खीरवाल,सारिका सिंह,पुजा केसरी,कृति बुधिया,शीतल ड्रोलीया,मनीषा सोमानी एवं अन्य मौजुद थे। आगे भी संस्था द्वारा विभिन्न तरह के सामाजिक कार्य किये जायेंगे।

जेसीआई ने वर्टिकल गार्डन लगाया

राँची :जेसीआई इंडिया का जेसीआई वीक के तहत रातु रोड स्थित राणी सती विद्यालय के दिवाल पर वरटीकल गार्डन लगाया गया एवं छात्रों के बीच सीड्स का भी वितरण किया गया। जेसीआई के सदस्यों ने छात्रों को पर्यावरण का संरक्षण हेतु उन्हें जागरूक भी किया गया तथा उन्हें बीज देकर संकल्प दिलाया गया की वे अपने घरों में सीड्स को लगायेंगे।कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजिका नितीशा जालान, ऊडान की अध्यक्ष आभा भंडारी,विनीता जैन एवं अन्य सदस्य मौजुद थे।

देश में प्रति दिन हजारो लोग कृषि में फायदा नही देख महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

कृषि को लाभ का व्यवसाय कैसे बनायेगी सरकार ?

आस्ट्रेलिया अमेरिका में ज्यादा उपज होने पर उन्हें और ज्यादा मात्रा मे निर्यात किया जाता है। हमारे यहां बंपर फसल होने पर उसकी कीमत कौड़ी के भाव पर आ जाती है।किसानों को सरकार को राहत देनी पड़ती है। अक्सर मदद न मिलने पर किसान सड़क पर हीं अपनी उपज को फेंक कर चल देता है। अच्छी उपज के बाद एक किसान जब कोल्ड स्टोरेज का रूख करना चाहता है तो, उसे वहां जगह नहीं मिलता। कोल्ड स्टोरेज बड़े या जमींदार किसानों के लिये हैं। हार कर किसान औने पौने दामों में या लागत से भी कम कीमत पर फसल बेच देता है। रांची में ही रूक्का में फूड प्रोसेसिंग प्लांट बना, लेकिन शीतलक के समय पर नहीं लगने से यह प्लांट चालू नहीं हो सका। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह स्थिति बहुत ही दुखद है। तो क्या कृषि यहां मजबूरी का व्यवसाय बन गया है?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन में बताया कि भारत अगले 11 सालों में 2030 तक 2 करोड़ 6 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बना देगा। भारत में अधिकांश मरुस्थलीय भूमि राजस्थान में है। इसका दायरा सीमित है। इसके अलावा अन्य भागों मे भी काफी भूमि कई प्राकृतिक व कृत्रिम कारणों से बंजर पड़ी हुई है। जिस पर खेती नहीं हो सकती है। कृत्रिम रूप से बंजर जमीन जंगलों की कटाई के कारण हो रही है। घने जंगलों के अंदर जाकर पेड़ों को काट दिया गया है जो नजर से ओझल रहता है। कई इलाके पथरीले हैं- लेकिन दूसरे रूप में उपयोगी है। इन्हें पत्थरों की खुली खदान कहा जाता है। देश के विकास में पत्थर का काफी बड़ा योगदान रहता है। गिट्टी और बजरी के अनेकों लाभदायी प्रयोग होते है। राजस्थान के भौगोलिक मरुस्थल को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन वहां से रेल व सड़क मार्ग से रेत का परिवहन भारत के अन्य भागों तक करके नदियों से रेत निकालने को खत्म किया जा सकता है। जो नदियों को खासकर मध्यप्रदेश में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मरुस्थलों में रेत खुले में रहती है- यहां खदान की तरह या नदियों की रेत की तरह इसकी खुदाई नहीं करनी होगी। वह विशाल मात्रा में खुले में रहती है। केवल उसकी ढुलाई का खर्चा आयेगा। समुद्र तटों से खासकर गुजरात व तमिलनाडु सें जहां देश का अधिकांश नमक बनाया जाता है और उसे भारत के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। इसी तरह रेत भी प्राकृतिक मरुस्थल से सप्लाई की जा सकती है। रेत का अवैध व्यापार, चोरी और नदियों के विनाश को रोकने के लिये मरुस्थल में बेकार पड़ी रेत को व्यापारिक महत्व की बनाया जा सकता है। जंगल कटाई रोकने व वनीकरण को गति देकर न सिर्फ जलवायु को पुनः स्वस्थ बनाया जा सकता है बल्कि इससे मरुस्थलों को भी आगे बढने से रोका जा सकता है और जहां भूमि बन्जर हो गई है उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है।इस संदर्भ में 'बंजर भूमि और 'मरुस्थल की भूमि दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। बंजर भूमि मरुस्थल नहीं है। संसार में फैले भौगोलिक व प्राकृतिक मरुस्थल संसार में सबसे ज्यादा अरब राष्ट्रों में हैं और वहां भी इन्हीं मरुस्थलों में ही दुनिया का काला सोना पेट्रो क्रूड पाया जाता है। जिसने दुनिया को गति दी है और वह जीवन और विकास की नितान्त आवश्यक वस्तु बन चुका है।अरब देशों के मरुस्थल रेत के रूप में ही वरदान है। इन्हें पेट्रो क्रूड के खेत और उसकी उपज कहा जाना चाहिए। राजस्थान, गुजरात के मरुस्थलों में पेट्रो क्रूड की खोज की जानी चाहिए। कहा जाता है कि प्रकृति की कोई चीज निरर्थक नहीं है। संसार की सारी वनस्पति औषधि व रसायन है। इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया एक विलक्षण देश है। इसका 80 प्रतिशत भाग बंजर भूमि है। बीस प्रतिशत भाग जो चारों तरफ समुद्र तटों पर है वही उपजाऊ है। आस्ट्रेलिया के सभी नगर इसी 20 प्रतिशत भूमि पर समुद्र तटों पर बसे है। इसके बावजूद भी आस्ट्रेलिया इतनी कम जमीन पर इतना ज्यादा गेहूं पैदा करता है कि वह व्यापार और उसकी अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत जैसा कृषि प्रधान देश जहां सबसे ज्यादा कृषि की उपजाऊ भूमि है, उसने आजादी के बाद कई वर्षों तक खाद्यान्न के अभाव में आस्ट्रेलिया से गेहूं लिया है।भारत में आज भी आटा मिलें आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करती है क्योंकि उन्हें अपने घर भारत के गेहूं से आस्ट्रेलिया का गेहूं सस्ता पड़ता है। कृषि प्रधान भारत कृषि के क्षेत्र में अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। किसान की आय दुगनी करने की सरकार की नीति और लक्ष्य है तो कृषि को आधुनिक रूप से विकसित करना होगा बल्कि उसका व्यापार भी सुधारना होगा। यह भी विडम्बना है कि जब गेहूं या अन्य अनाजों के साथ सब्जियों में आलू-प्याज-लहसुन की बम्पर फसलें आती हैं तो उनके भाव क्रेश हो जाते हैं और किसान को सरकार समर्थन या राहत खरीदी से सहारा देना होता है। आस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में गेहूं, दालों का निर्यात उनका विश्व मंडी में विकसित व्यापार है। भारत में बम्पर फसलें किसान और सरकार दोनों की मुसीबत बन जाती है। ऐसी स्थिति व परिस्थिति में खेती को कैसे लाभ का धंधा और किसानों की आमदनी दुगनी की जा सकती है?

जेएससीए स्टेडियम में भी रथिन भद्रा और राजा बागची ने खास तकनीक से जल संकट दूर किया

भूंगरू वह नायाब तकनीक जो जलसंकट को कर सकता है समाप्त

रांची :हर साल गर्मियों में रांची में जलसंकट गहरा जाता है। पर्याप्त बारिश, राजधानी के आस पास स्थित तीन बड़े डैम के बाद भी आखिर क्या कारण है कि मार्च के शुरूआत से ही रांची का एक बड़ा इलाका जलसंकट से घिर जाता है। बढती आबादी, नदी नालों का अतिक्रमण तो कारण है हीं इसके अलावा कुछ ऐसे तकनीकी कारण भी रहे हैं जिससे रांची सहित झारखंड में गर्मियों में जल की कमी होती है।

कभी रांची की शान रहे जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी की कमी के कारण उसकी हरियाली समाप्त हो गयी थी और स्टेडियम मैच कराने लायक नहीं रह गया था। सारे बोरिंग फेल हो गये थे।ऐसी स्थिति में रथिन भद्रा और राजा बागची ने अपने जलसंरक्षण तकनीक भूंगरू के माध्यम से स्टेडियम के बोरिंग को चार्ज कर वहां से जल की कमी को सफलता पूर्वक दूर किया। इसके अलावा भी कई जगहों पर इस तकनीक से इन्होंने सफलतापूर्वक जलसंकट का निदान किया है।

क्या है भूंगरू

भूंगरू दरअसल आदिवासियों के देवता का नाम है। तमाड़ में एक तालाब भी था जिसे भूंगरू तालाब कहते थे, और इसकी बहुत ही धार्मिक मान्यता थी। इसी कारण से जलसंरक्षण के इस तकनीक का नाम भी भूंगरू रख दिया गया।

झारखंड की धरती के नीचे ऐसी कठोर चट्टानें हैं जहां जल संग्रह करना तकनीकी और श्रमसाध्य काम है : रथिन भद्रा

समूचे झारखंड की धरती में नीचे सॉलिड चट्टानें हैं और इसमें वर्तमान में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना कर जलसंरक्षण का प्रयास किया जाता है उसका सही परिणाम नहीं मिलता। यहां बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जांच कर के ही धरती में वहीं जल संचय हो सकता है जहां दरारें हो, पानी एकत्र करने लायक खोह हो। इन सभी बातों को बिना जांचे अगर हम कोई पिट, गड्ढा बना कर उसमें जल एकत्र करते हैं तो वह सारा जल अंदरूनी रूप से बह कर किसी गैरउपयोगी जगह पर चला जाता है और जरूरी जगह अंदरूनी तौर पर जलरहित ही रह जाता है। यही कारण है कि, यहां हजार फुट पर भी बोरिंग फेल हो जाते हैं। रांची में ही तकरीबन 22 हजार अपार्टमेंट हैं और नियमानुसार सबों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा रहा है फिर भी पानी का स्तर सुधर नहीं रहा तो इसका मुख्य कारण यहां की धरती में उन कठोर चट्टानों का होना है जो किसी खास जगह पर जल संचयन में बाधक हैं। वास्तव में आज जदतर जगहों से हम पानी निकाल तो रहे हैं, पर पानी स्टोर करने का काम नहीं कर रहे।

कैसे काम करता है भूंगरू तकनीक?

जहां भी जल संरक्षण करना हो पहले वहां अच्छी तरह से रेकी की जाती है। रेकी में कई सुक्ष्म चीजें तक देखी जाती हैं। जैसे पहले कभी वहां पानी था कि नहीं?अगर वहां केले का पेड़ है तो जल संचयन की अच्छी संभावना बनती है। साथ ही वहां कीड़े मकोड़ों की प्रजाति भी देखी जाती है जो जल संचय के सूचक होते हैं। इसके बाद जियोफिजिकल स्टडी की जाती है। सैटेलाइट से सर्वे करते हैं। इससे उस क्षेत्र में वैसे स्पॉट का पता चल जाता है जहां जल एकत्र किया जा सके। उसके बाद वहां बोरिंग की जाती है। उस बोरिंग में भी एक खास किस्म के छिद्रयुक्त पाइप को डाला जाता है। इसमें इंजेक्सन मॉडयूल लगा होता है। यह जल को उस क्षेत्र में इंजेक्ट करता है।

भूंगरू में तकनीक कुछ ऐसी है कि, हार्वेस्टिंग वाले क्षेत्र में इंजेक्सन मॉडयूल के माध्यम से पानी के बुलबुलों को इंजेक्ट किया जाता है इससे धरती के अंदर पानी का एक अंदरूनी तालाब निर्मित हो जाता है। उस क्षेत्र के ढलानों पर बनाया गया छोटा सा भी सक्सन यूनिट जिसमें फिल्टर के लिये काष्ठकोयला, तक उपयोग किया जाता है इतना कामयाब हो जाता है जो पानी के निकाल लेने पर तुरंत ही वहां फिर से जल की उपस्थिति बना देता है। इस तकनीक को सफलतापूर्वक रांची कॉलेज के आदिवासी हॉस्टल में उपयोग किया जा रहा है जिससे वहां जलसंकट समाप्त हो गया है।

भारतीय गेहूं में प्रोटीन की मात्रा इतनी कम है कि, अंतराष्ट्रीय बाजार में इसकी कोई मांग ही नहीं, भले हम फसल ज्यादा उगा रहे हैं पर उसकी गुणवत्ता में कमी है

दुनिया में बेचने लायक नहीं है हमारे खाद्यान्नों की क्वालिटी

संजय कुंदन

आजकल अक्सर भारतीय खेती के संकट की चर्चा होती है। खेती से किसानों का मोहभंग होता जा रहा है क्योंकि इससे उनकी दाल रोटी भी ठीक से नहीं चल पा रही। खेती के संकट का एक आयाम यह भी है कि यह व्यावसायिक नहीं हो पाई। हम इतना नहीं उपजा पा रहे कि खूब निर्यात कर सकें। और अगर उपजा भी ले रहे हैं तो हमारे खाद्यान्नों की क्वालिटी ऐसी नहीं हो पा रही कि हम उन्हें दुनिया भर में बेच सकें। पिछले दिनों पता चला कि भारतीय गेहूं विश्व बाजार में पिछड़ रही है। इसका कारण यह है कि उसमें प्रोटीन की अपेक्षित मात्रा ही नहीं है। दशकों की मशक्कत के बाद भी गेहूं की घरेलू प्रजातियों में प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ पाई है। कहने को तो भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों की सूची में शुमार है। हरित क्रांति के बाद भारत में इसकी पैदावार

में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसकी साढ़े चार सौ प्रजातियां विकसित की गईं जिसका नतीजा निकला कि भारत गेहूं में आत्मनिर्भर देश बन गया और इसका निर्यात भी करने लगा लेकिन गुणवत्ता में कमी होने के कारण यह अंतराष्ट्रीय बाजार में नहीं टिक पाती। घरेलू गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 12 फीसद की सीमा को नहीं छू पाई है। वैश्विक मानक के अनुरूप गुणवत्ता न होने की वजह से घरेलू गेहूं की निर्यात मांग न के बराबर है। कुछ एशियाई व अफ्रीकी देशों को छोड़कर और किसी देश में भारतीय गेहूं की मांग नहीं है। जाहिर है यह हमारे लिए भारी चिंता का विषय है। इस मसले पर इंदौर में 'अंतरराष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान कार्यकर्ता सम्मेलन' में इस पर गंभीर चर्चा होगी। घरेलू गेहूं में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के साथ कई और मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा जैसे जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले रोगों की चुनौतियां भी इसका हिस्सा होंगी। फिलहाल दुनियाभर में 'व्हीट ब्लास्ट' जैसे घातक रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। यह रोग भारत तक नहीं पहुंचा है लेकिन बांग्लादेश में इसके प्रकोप की सूचना है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के तीन-चार जिलों में गेहूं की खेती पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे लेकर सरकार पूरी मुस्तैदी बरत रही है। जाहिर है हमें अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देना होगा बल्कि फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी प्रयास करना होगा।

डीसी मंडल हाइकोर्ट अधिवक्ता लिपिक संघ के अध्यक्ष चुने गये

रांची : डीसी मंडल झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता लिपिक संघ के अध्यक्ष चुने गये हैं। डीसी मंडल ने दोबारा इस पद के लिये जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतक प्रतिद्वंदी विनय कुमार को 71 वोटों से पराजित किया। अध्यक्ष पद के लिये मुकाबले में कुल चार प्रत्याशियों में डीसी मंडल ने सर्वाधिक 128 वोट प्राप्त किये।

क्या बैन हो पायेगा प्लास्टिक?

एकल प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों और खतरों को देखते हुये सारे देश में इस पर रोक के प्रयास चल रहे हैं और दुर्भाग्य कि यह सारे प्रयास असफल हुये हैं। इस समस्या की भयावहता का अंदाजा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक को एकल प्लास्टिक पर रोक के लिये आह्वान करना पड़ा है। लेकिन इस पर बैन अब तक संभव नहीं हो पाया है। इस असफलता का कारण भी स्पष्ट है। यह दुखद तथ्य है कि हमने इसके कारण पर चोट करने के बजाय सिर्फ इसके उपयोग को रोकने का प्रयास किया। कारण है इसका अनवरत बेरोकटोक उत्पादन और बड़ी छोटी कंपनियों में इसका धड़ल्ले से उपयोग। हर साल फुटपाथ के दूकानों से लेकर छोटे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पॉली बैग के उपयोग के खिलाफ छापेमारी होती है उन्हे जुर्माने लगाये जाते हैं, पर कुछ दिन या सप्ताह के बाद प्लास्टिक और उसके कैरी बैग फिर से खुल कर उपयोग होने लगते हैं। दशक भर से ज्यादा समय से प्लास्टिक पर बैन का प्रहसन चल रहा है लेकिन यह पूरी कवायद फेल होती रही है। हम आप सभी इसके कुप्रभाव पर चिंता तो व्यक्त करते हैं, पर रेहड़ी ठेले वाले से लेकर बड़े दूकानों में कभी इसमें सामान लेने से मना नहीं करते। दूसरा कारण है कि दूकानों में छापेमारी के बजाय इसके उत्पादन को बंद करने पर कभी जोर नहीं दिया गया। अगर कारखानों में पॉलीबैग बनाने पर कड़ी सजा का प्रावधान हो तो इस समस्या के मूल पर ही कड़ा प्रहार होगा।

> हालात ऐसे हैं कि, आप झोला लेकर भी बाजार जायें तो दूकानदार के हाथ खुद प्लास्टिक के थैलों की ओर चले जाते हैं और आप झोले में भी प्लासिटक बैग में पैक किया सामान लेकर आते हैं। बर्तन से लेकर हमारे खाने की चीजों में भी इसका कब्जा हो गया। आज हालात ये है कि आम भारतीय किसी न किसी रूप में हर रोज प्लास्टिक की कुछ मात्रा खा रहा है और भयंकर व्याधियों का शिकार हो रहा है। चाय कॉफी की प्लेट हो या ठेले से पार्सल भोजन सब कुछ में प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। गर्म भोजन प्लास्टिक को घुला देता है जो हमारे भोजन का हिस्सा बन जाता है।

प्लास्टिक की एक खासियत है कि यह लो मेल्टिंग प्वाइंट का पदार्थ है और इसे पिघला कर हम जिस आकार में चाहें उस आकार में आसानी से ढाल सकते हैं। अपने इस गुण के कारण प्लास्टिक हमारे उपयोग के हर चीज में प्रवेश कर गया। किसी भी आयोजन में शादी विवाह में प्लास्टिक के ग्लास और कप प्लेट का खुल कर उपयोग होता है। चुकि यह एकल उपयोग वाले होते हैं इस कारण सैकड़ो लोग इनका उपयोग कर के यत्र तत्र फेंक कर चल देते हैं और प्रायः समापन के बाद वहां सर्वत्र प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आता है। इसके बाद अगर ठिक से साफ सफाई नहीं हुयी तो यह प्लास्टिक वहां सैकड़ो साल तक काबिज रह सकता है। कई महानगरों तक में सीवरेज और ड्रेनेज की जाम के समस्या के पीछे यही प्लास्टिक कैरी बैग है। लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक है प्लास्टिक का हमारे भोजन में घुलना। चाय कॉफी के कप और छोटे ग्लास तक प्लास्टिक के उपयोग हो रहे हैं। छोटे बड़े रेस्टोरेंट तक में प्लास्टिक के कैरी बैग में गर्म खाने को पैक किया जाता है। यह गर्म खाना प्लास्टिक को घुला कर खुद में अवशोषित कर लेता है। ठिक वैसे ही चाय कॉफी के प्लास्टिक ग्लास भी गर्म पेय के संपर्क में आते ही घुल कर चाय या कॉफी में मिल जाते हैं। ये सभी सीधे हमारे पेट में जाते हैं और अंततः कैंसर का कारण बनते हैं।

भारत में जहां स्वास्थ्य को लेकर आम जन पहले से ही काफी लापरवाह है वहां ये प्लास्टिक देश का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है।आप गौर करें तो बाजार का प्रत्येक उत्पाद प्लास्टिक में पैक है और इनमें से ज्यादतर ऐसे हैं जो अंततः हमारे शरीर और पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। पशुओं में बीमारी , कम दूध देना और उनकी असमय मौत का कारण माइक्रो प्लास्टिक हैं। किसी पर्यावरणविद् ने भी कहा है कि हम भारतीय शाकाहार या मांसाहारी हों न हों हम सभी प्लास्टिकआहारी अवश्य हैं। एक अरब से ज्यादा की आबादी आज इसका शिकार है, बिना सजग हुये इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रही है। जब तक जनता खुद प्लास्टिक के खतरनाक उत्पादों के उपयोग से इनकार नहीं करेगी और इनके निर्माण को रोका नहीं जायेगा तब तक एकल प्लास्टिक पर रोक महज प्रहसन बन कर रह जायेगा।

क्या फुकुशिमा का रेडियोधर्मी पानी महासागर में बहाया जाएगा?

जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का संचालन करने वाली कंपनी का कहना है कि उसके पास अब और रेडियोधर्मी पानी को रखने की जगह नहीं है। सरकार और लोगों पर कंपनी इस समस्या के समाधान के लिए दबाव बना रही है।यह वही संयंत्र है जो 2011 में एक साथ आए सूनामी और भूकंप की चपेट में आया था। उस आपदा में फुकुशिमा दाई ची परमाणु संयंत्र के तीन रिएक्टर पिघल गए थे। इसके बाद रिएक्टर से रेडियोधर्मी पानी रिस कर संयंत्र के पास भूजल और बारिश के पानी में मिल गया। हालांकि इस पानी को साफ किया जाता है लेकिन फिर भी यह रेडियोधर्मी होता है। इस पानी को बड़े बड़े टैंक में जमा कर रखा जाता है। फुकुशिमा संयंत्र ने एक हजार टैंकों में 10 लाख लीटर से ज्यादा पानी जमा कर रखा है। संयंत्र को संचालित करने वाली कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कहना है कि उसकी योजना और ज्यादा टैंक बनाने की है जिसके बाद वह 13 लाख 70 हजार लीटर पानी जमा करके रख पाएगी। कंपनी के पास 2022 तक इतना पानी जमा हो जाएगा। हालांकि इसके बाद क्या होगा यह बड़ा सवाल है। फुकुशिमा पर आई आपदा के करीब साढ़े आठ साल बीत चुके हैं लेकिन अब भी अधिकारी इस बात पर सहमत नहीं हो सके हैं कि इस रेडियोधर्मी पानी का क्या किया जाए। सरकार के बनाए एक पैनल ने पांच विकल्प चुने हैं। इनमें एक विकल्प यह भी है कि नियंत्रित रूप से पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ा जाए। परमाणु विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य मानते हैं कि यही एक व्यवहारिक विकल्प बचा है। हालांकि इस इलाके में रहने वाले लोग और मछुआरे

इस विकल्प का विरोध कर रहे हैं।उनका कहना है कि पानी को सागर में डालना फुकुशिमा में मछलीपालन और कृषि के लिए आत्मघाती होगा।विशेषज्ञों का कहना है कि इन टैंकों की वजह से यहां बाढ़ और विकिरण का खतरा है और साथ ही यह संयंत्र को बंद करने की कोशिशों के भी खिलाफ है। टेपको और सरकारी अधिकारी पिघले हुए ईंधन को 2021 में बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि इस परिसर को इन टैंकों से मुक्त कराया जाए ताकि पिघल कर बाहर निकलने वाले कचरे और दूसरे जहरीले तत्वों के लिए के लिए सुरक्षित भंडार बनाए जाएं। पैनल ने चार अन्य विकल्पों के अलावा लंबे समय के लिए भंडार की योजना को पांचवे विकल्प के रूप में शामिल किया है। पैनल के कई सदस्यों ने टेपको से आग्रह किया है कि वह और जमीन अधिग्रहित करने के बारे में सोचे ताकि जल्दी ही सहमति नहीं बनने की स्थिति में और ज्यादा टैंक बनाए जा सकें। टेपको के प्रवक्ता जुनिशी मातसुमोतो का कहना है कि प्लांट को बंद करने के बाद निकलने वाले जहरीले पदार्थों को इस परिसर में ही रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि लंबे समय तक भंडारण करने से रेडियोधर्मिता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि इनकी उम्र आधी ही रहती है। हालांकि इससे प्लांट को बंद करने के काम में बाधा आएगी। मातसुमोतो ने इस इस रेडियोधर्मी पानी पर फैसले लिए कोई समयसीमा तय करने से मना कर दिया लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही इस पर लोगों के बीच बहस कराएगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय लोगों की भावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सौरमंडल से बाहर पहला ग्रह, जहां बारिश होती है

क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या पृथ्वी से बाहर कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी मौजूद हैं या नहीं, या फिर यह कि क्या सचमुच आकाश में कोई ऐसी जगह है जहां से रहस्यमय एलिएन उड़नतश्तरी पर सवार होकर आते हैं, तो इस नए विज्ञान के पास हमारी जिज्ञासा शांत करने वाला कोई जवाब फिलहाल मौजूद नहीं है।

चंद्रभूषण

धरती से बाहर जीवन की संभावनाओं की तलाश एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। सन 2015 में केपलर टेलिस्कोप द्वारा 111 प्रकाशवर्ष दूर खोजे गए ग्रह के2-18बी पर खगोलशास्त्रियों की दो टीमों ने बरसाती बादलों की शिनाख्त की है। इसी हफ्ते घोषित की गई यह खोज दुर्लभ ह। हालांकि साथ में उन्होंने इस ग्रह को पृथ्वी जैसा मान लिए जाने के अतिरेक को लेकर आगाह भी किया है। सौरमंडल से बाहर ग्रहों की तलाश में हमारे सामने अभी कुछ बड़ी तकनीकी बाधाएं मौजूद हैं। केपलर टेलिस्कोप ने इन बाधाओं से काफी हद तक मुक्ति दिलाई है। इसकी मेहरबानी से खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स (सूर्य के अलावा अन्य तारों के ग्रहों) की संख्या देखते-देखते सैकड़ों से बढ़कर हजारों में (अभी चार हजार से ज्यादा) पहुंच गई है। हबल टेलिस्कोप से लिए गए के2-18 तारे के स्पेक्ट्रम के अध्ययन से पता चला कि इस ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम और पानी की भाप मौजूद है। 111 प्रकाशवर्ष की विराट दूरी पर इतने संश्लिष्ट रूप में पानी का दर्ज किया जाना खुद में एक चमत्कार है। हालांकि बादलों के प्रेक्षण भर से इसकी सतह पर जीवनदायिनी बरसात होने का अनुमान लगाना तथ्यों से आगे बढ़कर कहानियों में जाने जैसा होगा। ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तो हम यही नहीं जानते कि उक्त ग्रह की कोई ठोस सतह है भी या नहीं। तारा के2-18 वजन में सूरज का 40 फीसदी है और इसका तापमान सूरज का लगभग आधा है। इसका घनत्व पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। तारे में धातुएं कम होने से ग्रह में भी धातुओं का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन घनत्व कम होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि ग्रह का कोर और बाकी ठोस हिस्सा छोटा हो और उसकी बनावट में पानी का हिस्सा काफी बड़ा हो। ऐसे में यह संभव है कि ग्रह की सतह पृथ्वी की तरह चट्टानी न हो। इससे जुड़ी कई उत्सुकताओं का समाधान 2021 में छोड़े जाने वाले जस्टिन वेब टेलिस्कोप के प्रेक्षणों से हो जाएगा। और अगर वहां इवॉल्यूशन की संभावना मौजूद हुई तो इसके लिए समय कोई समस्या नहीं है। के2-18 जैसे लाल बौने तारों की उम्र सूरज की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इतनी कि कुछ वैज्ञानिक इन्हें अमर तारे कहने में भी संकोच नहीं करते।

डिस्क्लेमर : ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं

घूमने फिरने, पर्यटन और एडवेंचर के शौक के कारण हिमालय पर मनुष्यों और वाहनों की भीड़ ने पहले से ही हलकान हिमालय के लिये समस्या खड़ी कर दी है

हिमालय को मानवाधिक्य से बचाना होगा

जयसिंह रावत

> भिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं वाले मानव समूहों में वर्चस्व को लेकर चले संघर्षो से निजात पाने के लिए जब कुछ मानव समूह हिमालय की ओर आए होंगे तो उन्होंने हिमालय की कंदराओं को सबसे सुरक्षित ठिकाना पाया होगा। इसीलिए कालीदास ने अपने महाकाव्य "कुमारसंभव' में हिमालय को "धरती का मानदंड' और "दुनिया की छत और आश्रय' बताया था। लेकिन इस हिमालय पर निरंतर बढ़ती आपदाओं के कारण यह आश्रय सुरक्षित नहीं रह गया है।

इस बार मॉनसूनी आपदाओं में हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह तक 63 लोगों की जानें चली गई थीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 20 अगस्त को विधानसभा में बताया कि उस दिन तक बरसात में प्रदेश को लगभग 625 करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी थीं। उत्तराखंड में सालाना औसतन 110 लोग ऐसी आपदाओं में जान गंवा देते हैं। जम्मू-कश्मीर में तवी नदी हर साल बौखला जाती है। असम में इस साल बाढ़ से धेमाजी, बारपेटा, मोरीगांव, होजई, जोरहाट, चराइदेव और डिब्रूगढ़ जिलों के कई गांवों की 17,563 हेक्टेयर से अधिक फसल जलमग्न हो गई। हिमालय में ऐसी त्रासदियों का लंबा इतिहास है। लेकिन इन प्राकृतिक विप्लवों की बारंबारता में जो तेजी है, निश्चित ही चिंता का विषय है। लेह में 5 एवं 6 अगस्त, 2010 की रात बादल फटने से आई त्वरित बाढ़ और भूस्खलन में 255 लोग मारे गए। उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाएं आम हैं। 1977 में ऐसे हादसे में तवाघाट में 25 सैनिकों सहित 44 लोग मारे गए थे। 1996 में बेरीनाग में 18 लोग मारे गए। 1998 के अगस्त में मालपा में बाढ़ से 60 मानसरोवर यात्रियों सहित 250 और उखीमठ में 101 लोग मारे गए थे। हड़की में 2000 में 19, घनसाली और बूढ़ाकेदार में 2002 में 29, बरहम में 2007 में 18; जून, 2008 में हेमकुंड में ग्लेशियर फटने से 14, अगस्त, 2009 में पिथौरागढ़ के रोमगाड़, चासनी व नागड़ी गांवों में बादल फटने से 43, अगस्त, 2010 में कपकोट के सुमगढ़ में स्कूल पर मलबा आने से 18 बच्चे और सितम्बर, 2010 में अल्मोड़ा देवली में बादल फटने से 35 लोग मारे गए थे। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2013 की मॉनसून आपदा में 4200 गांवों की 5 लाख आबादी पीड़ति हुई है। इनमें से 59 गांव तबाह हो गए। शुरू में 4,459 लोगों के घायल होने तथा 5466 के लापता होने की रिपार्ट आई थी, मगर गैर-सरकारी अनुमानों में मृतकों की संख्या 15 हजार से अधिक मानी गई। हिमाचल में त्वरित बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने एवं भूकंप की दृष्टि से चम्बा, किन्नौर, कुल्लू जिले पूर्ण रूप से और कांगड़ा और शिमला जिलों के कुछ हिस्से अत्यधिक संवेदनशील माने गए हैं। दुनिया की इस सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के ऊपर निरंतर प्राकृतिक आपदा हो रहे हैं तो इसका भूगर्भ भी अशांत है। असम में 1897 में 8।7 और 1950 में 8।5 परिमाण और हिमाचल के कांगड़ा में 7।8 परिमाण के भीषण भूचाल आ चुके हैं।

कांगड़ा के भूकंप में 20 हजार लोग और 53 हजार पशु मारे गए थे। भूकंप विशेषज्ञों का मानना है कि पिछली सदी में इस क्षेत्र में कोई बड़ा भूचाल न आने से भूगर्भीय ऊर्जा जमीन के नीचे जमा होती जा रही है। जिस दिन वह बाहर निकली तो कई परमाणु बमों के बराबर विनाशकारी साबित हो सकती है। भूगर्भविद् के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला अभी भी विकासमान स्थिति में है और भूकंपों के सर्वाधिक असर में है। इसका दुष्प्रभाव यहां स्थित हिमानियों, हिम निर्मित तालाबों और चट्टानों और धरती पर पड़ता रहता है। इस कारण नदियों की बौखलाहट बढ़ी है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हिमखंड के बढ़ने-घटने के चक्र में बदलाव शुरू हो गया है। दरअसल, हिमालय पर अत्यधिक मानव दबाव के कारण सिंधु से लेकर ब्र१पुत्र तक की लगभग 2400 किमी लंबी इस पर्वतमाला को भूकंप, भूस्खलन, त्वरित बाढ़, आसमानी बिजली गिरने, बादल फटने एवं हिमखंड स्खलन जैसी आपदाओं ने अपना स्थायी घर बना लिया है। हिमालयी राज्यों में देश का लगभग 25 प्रतिशत वन क्षेत्र है। किंतु पिछले दो दशकों में उत्तर-पूर्व के हिमालयी राज्यों में निरंतर वनावरण घट रहा है।

विकास के नाम पर प्रकृति से बेतहाशा छेड़छाड़ हो रही है। पर्यटन और तीर्थाटन के नाम पर हिमालय पर उमड़ रही मनुष्यों और वाहनों की बेकाबू भीड़ भी संकट को बढ़ा रही है।

तैयार किए जाएं हजारों युवा पर्यावरण कार्यकर्ता

संजय कुंदन

पर्यावरण के संकट की तरफ बार-बार ध्यान दिलाया जा रहा है। अब इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से निपटे बिना हम चैन से नहीं रह सकते। इसका दुष्प्रभाव हम साफ देख रहे हैं कि देश में एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ बाढ़ आई हुई है। इस संकट से निपटने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है। इसमें हर व्यक्ति को लगना होगा। हर आदमी के दिमाग में यह घुसा देना है कि जलवायु परिवर्तन से जूझने में हमारा भी रोल है। इसका एक तरीका यह है कि बच्चों को शुरू से ही यह एक जरूरी पाठ के रूप में पढ़ाया जाए ऐसी कोशिशें एक हद तक शुरू हो भी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने तरीके से पहल की है। बच्चों को तो नहीं लेकिन युवाओं को वह इस महा अभियान से जोड़ने जा रहा है। इसी मकसद से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अगले महीने पहला युवा जलवायु सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए भारत के पी।आर।विष्णु को चना गया है। वह दुनिया भर से चुने गए उन 100 युवा पर्यावरण कार्यर्ताओं में से हैं, जिन्हें इस सम्मेलन के लिए विशेष 'ग्रीन टिकट मिला है। पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 100 'ग्रीन टिकट विजेता' 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में आयोजित पहले युवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 500 युवा पर्यावरण नेताओं के साथ शामिल होंगे।

यह सम्मेलन युवा पर्यावरण नेताओं को जलवायु परिवर्तन रोकने के उपायों को प्रदर्शित करने और नीति निर्माताओं से सीधे संपर्क करने का मौका देगा।

शाम में टहलना ज्यादा लाभदायक

रांची : ज्यादातर लोग सुबह उठ कर सैर करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि सुबह की ताजा हवा सेहत के लिए बेहद लाभकारी होती है। डॉक्टरों का भी कहना है कि सुबह की चहलकदमी से कई तरह के फायदे होते हैं। पर साथ में वे कहते हैं कि अगर सुबह मुमकिन न हो पाए, तो शाम को जरूर पैरों को थोड़ा अभ्यास करा देना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए कुछ हजार कदम हर रोज चलना जरूरी है। शाम को टहलने वाले निश्चिंत होकर निकलते हैं।और तनावमुक्त रहते हैं। वहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि सुबह में टहलना जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को रास आये। बहुत सारे लोग सुबह में टहलने पर कई तरह की शारीरिक समस्याओं की शिकायत करते हैं। वैसे लोगों को डॉक्टर धूप उगने पर घूमने की सलाह देते हैं। दरअसल हृदय रोग से ग्रस्त लोगों के लिये अहले सुबह उठ कर टहलना खतरनाक भी हो सकता है।

पृथ्वी पर खेती योग्य भूमि को बंजर बनने से रोकने के मुद्दे पर इस बार हुये कॉप सम्मेलन के अंत में हुये घोषणापत्र से हुयी मायूसी

चिंतन कॉप-14: घोषणा पत्र से गायब हुए दो अहम मुद्दे

- मरूस्थलीकरण रोकने के लिये राशि देने वाली एजेंसियों का कोई जिक्र नहीं
- वनों को बचाने वाले वनवासियों को भूमि अधिकार देने के प्रस्ताव को घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं किया गया।

ईशान कुकरेती

नई दिल्ली घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वनवासियों को अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया।

यूएनसीसीडी कॉप 14 के समापन अवसर पर भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। यूएनसीसीडी कॉप 14 के समापन अवसर पर भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। यूएनसीसीडी कॉप 14 के समापन अवसर पर भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। धरती को बंजर बना रहे मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र संस्था का सम्मेलन (यूएनसीसीडी कॉप 14) शुक्रवार को समाप्त हो गया। समाप्ति के मौके पर नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र की खासियत यह रही कि मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए पैसा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का इसमें जिक्र ही नहीं है, जबकि इस सम्मेलन के मुख्य प्रस्तावों में इसे शामिल किया गया था। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि वनों को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले वनवासियों को भूमि का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव को भी अंतिम घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया है।

यूएनसीसीडी कॉप 14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 3 सितंबर से शुरू हुआ था। उस समय सम्मेलन (कॉप 14) के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसका ड्राफ्ट जारी किया गया था। इसमें दो अहम बातें थी। पहला, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह बनाया जाएगा, ताकि सभी देशों, खासकर विकासशील व गरीब देशों को पैसे की कमी महसूस न हो। सम्मेलन के दौरान जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि धरती को बंजर होने से रोकने के लिए लगभग 46 हजार करोड़ (6।4 बिलियन डॉलर) की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, मरुस्थलीकरण को रोकने में सबसे अहम भागीदारी जंगल निभाते हैं

और जंगल की सुरक्षा वहां के स्थानीय व वनवासी करते हैं। इसलिए उनको जमीन से संबंधित ऐसे अधिकार दिए जाएं, ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और जंगल को बचाने में अहम भूमिका निभा सकें। कॉप 14 के दौरान जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया भर के जंगलों की 70 फीसदी भूमि पर खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। जबकि एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया था कि स्थानीय व वनवासी समुदाय दुनिया के 40 फीसदी जंगलों को बचाए हुए हैं। बावजूद इसके उन पर बेदखली का संकट बना हुआ है। इस बारे में 9 सितंबर को ही डाउन टू अर्थ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें इन दोनों मुद्दों को सम्मेलन के एजेंडे से निकाले जाने का जिक्र किया था।

13 सितंबर को जारी अंतिम घोषणा पत्र में यह बात साफ हो गई कि इन दोनों मुद्दों को घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बनाया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए विकसित सदस्यों, निजी क्षेत्र व अन्य वित्तीय संस्थानों को निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिससे न केवल ग्रीन जॉब्स बढ़ेंगी, जमीन से पैदा होने वाले उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले जलवायु परिवर्तन पर बने अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जंगलों को बचना जरूरी है और यह काम स्थानीय समुदाय व वनवासी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसी का जिक्र यूएनसीसीडी ने भी किया था, लेकिन अंतिम घोषणा पत्र में इसे जगह नहीं दी गई है।

79 आश्रितों को दिया गया सीसीएल का नियुक्ति पत्र

पुर्व अभियोजित एवं लंबित मामलों पर माननीय न्यायालय के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में 14 सितम्बर को आयोजित "राष्ट्रीय लोक अदालत" में 79 आश्रितों को सीसीएल का नियुक्ति पत्र प्रदान गया । माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री एच.सी. मिश्रा की अध्यक्षता में माननीय न्यायधीश श्री सुजित नारायण प्रसाद, माननीय न्यायाधीश श्री संजय कुमार द्विवेदी, माननीय न्यायाधीश श्री के.पी. देव की तीन खंडपीठ स्थापित की गई थी । लोक अदालत के अंतर्गत स्थापित तीनो खंडपीठ ने उपयुक्त कार्यवाही करते हुए सीसीएल में नियुक्ति संबंधित पूर्व अभियोजित एवं लंबित विभिन्न मामलों पर निर्णय दिया । इस अवसर पर माननीय न्यायधीश श्रीमती अनुभा रावत चौधरी, माननीय न्यायधीश श्री ए.के. सिंह, माननीय न्यायधीश श्री अनंत विजय सिंह एवं विशिष्ट अतिथि सीएमडी, सीसीएल श्री गोपाल सिंह सहित सीसीएल मुख्यालय से महाप्रबंधक (विधि) श्री पार्थो भट्टाचार्जी, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ.सं.) श्री उमेश सिंह, महाप्रबंधक (औ.सं./विधि) श्री विजय कुमार, श्री गौतम कुमार चौधरी, श्री अविनाश श्रीवास्तव सहित सीसीएल कमांड क्षेत्रों व मुख्यालय के अधिकारीगण उपस्थित थे । इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों ने अपने हाथो से 79 आश्रितों को नियक्ति पत्र प्रदान किया ।

सीसीएल द्वारा आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया

''एक कदम प्लास्टिक वेस्ट मुक्त भारत की ओर'' के संदेश के साथ सीएमडी सीसीएल श्री गोपाल सिंह के मार्गदर्शन में सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 11 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2019 तक ''स्वच्छता ही सेवा'' मनाया जा रहा है । इसी कड़ी में आज बिरसा उंच्च विद्यालय, कांके, रांची में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीसीएल मुख्यालय से मुख्य प्रबंधक (सीएसआर) श्री के.ए. सुन्दर, मुख्य प्रबंधक (सीएसआर) श्री रवि प्रकाश, सहायक प्रबंधक (सीएसआर) श्रीमती निकिता भदानी, श्री प्रवीण कुमार एवं अन्य उपस्थित थे। बच्चों को अपने घर से सिंगल यूज प्लास्टिक जमा करने को कहा गया और जो सबसे अधिक जमा करेगा उसे पुरस्कृत किया जायेगा। साथ ही स्वच्छता से प्रेरित वीडियों दिखाया गया।

एक कदम प्लास्टिक वेस्ट मुक्त भारत की ओर

सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 11 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2019 तक ''स्वच्छता ही सेवा'' मनाया जा रहा है । इसी कड़ी में सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस परिसर, रांची में भारत सरकार द्वारा चलाये गये मुहिम 'स्वच्छता ही सेवा' का आयोजन किया गया। सीसीएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने उपस्थित सभी कर्मियों को 'स्वच्छता ही सेवा' एवं 'स्वच्छता की शपथ' दिलायी। इस अवसर पर सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री भोला सिंह, निदेशक (वित्त) श्री एन.के. अग्रवाल, मुख्य सतर्कता पदाधिकारी श्री ए.के. श्रीवास्तव सहित सीसीएल के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष तथा सीसीएल कर्मी उपस्थित थे।

उर्वरकों और मृदा स्वास्थ्य पर सरकार का रवैया विरोधाभासी

सुरिंदर सूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस ड्ढाषण में देश के किसानों से मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किसानों से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल रोकने या इसकी मात्रा कम करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान के कृषि क्षेत्र के लिए खास मायने हैं, इसलिए इसका सतर्कता से विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि रासायनिक प्रदूषण से मृदा स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता जायज है, लेकिन उनके द्वारा सुझाया गया समाधान मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। भूमि क्षरण और इसकी उर्वर शक्ति कमजोर करने के लिए केवल रासायनिक उर्वरक ही जिम्मेदार नहीं हैं। केवल इनका इस्तेमाल रोकने या इसमें कमी करने से समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। भूमि संसाधनों की हालत बिगाडने के लिए कई रासायनिक, भौतिक और जैविक कारक जिम्मेदार हैं। मई 2018 में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) की 'संक्षिप्त नीति' में इन कारकों पर चर्चा की गई है। एनएएएस ने इसके लिए अनुपयुक्त जोत, अकुशल कृषि योग्य भूमि एवं जल प्रबंधन, मृदा क्षरण, जल जमाव, लवणता एवं क्षार की उपस्थिति, उर्वरकों का असंतुलित इस्तेमाल, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी और सबसे अहम जैविक खाद के इस्तेमाल को नजरअंदाज करने जैसे कारकों को जिम्मेदार बताया है। हरित क्रांति से पहले रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता था। हालांकि उस समय उत्पादन भी कम था और बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए यह अपर्याप्त साबित हो रहा था। खाद्यान्न की कमी के मद्देनजर उर्वरकों के प्रति संवदेनशील ऊंची उपज देने वाली फसल किस्मों की पैदावार पर जोर दिया गया। यह पहल हरित क्रांति का जनक बनी और देश ज्यादातर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया। ऐसी ऊंची पैदावार देने वाली किस्मों के लिए अधिक मात्रा में मृदा पोषक तत्त्वों की जरूरत होती है, जिनकी आपूर्ति सामान्य जैविक खादों से नहीं की जा सकती है। वैसे ये जैविक खाद सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आपूर्ति में सहायक होते हैं, जो आम तौर पर रासायनिक उर्वरक नहीं कर पाते हैं। कृषि विशेषज्ञ कुल मिलाकर बेहतर परिणामों के लिए रासायनिक और जैविक खाद के मिले-जुले इस्तेमाल की सलाह देते हैं। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि सही मात्रा में सही समय पर और सही जगह पर रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है, न कि इसका ह्रास होता है।यह बात भी सही है कि उर्वरकों एवं मृदा स्वास्थ्य को लेकर सरकार का रवैया विरोधाभासी है। एक ओर सरकार रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने की सलाह देती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी खपत बढ़ाने के लिए इन पर भारी सब्सिडी (यूरिया के मामले में 70 प्रतिशत तक) देती है। सब्सिडी के साथ भी कुछ चिंताए हैं। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिए यह न तो व्यावहारिक है और न एकसमान है। इसका नतीजा यह होता है कि उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल से मृदा स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। इतना ही नहीं, फॉस्फेट, पोटाश और मिश्रित उर्वरक पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत लाए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला उर्वरक यूरिया इसकी जद में नहीं आता है। यूरिया की कीमत भी काफी कम रखी गई है, जो समझ से परे है। सब्सिडी को व्यावहारिक बनाना और यूरिया का विनियंत्रण कर इसे एनबीएस के तहत लाना पोषक तत्त्वों के संतुलित इस्तेमाल के लिए महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल रोकना और जरूरत भर इस्तेमाल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए भी गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रणाली और यूरिया की अनिवार्य नीम-कोटिंग ऐसे ही कुछ कदम हैं। अब अगले चरण में उत्पादन को प्रोत्साहन देने और रासायनिक उर्वरकों की तरह ही जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के लिए वित्तीय रियायत देने की जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने हाल में ही एक लिक्विड बायो-एनपीके फॉर्मूला तैयार किया है, जो मृदा को नुकसान पहुंचाए बिना तीनों मुख्य पोषक तत्त्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) की उपलब्धता बढ़ा सकता है। इस तरल फॉर्मूले में तीन तरह के अलग-अलग, लेकिन साथ-साथ काम करने वाले सूक्ष्मजीवी होते हैं। इनमें एजोटोबैक्टर क्रूकोकम वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन मृदा में अवशोषित होने में मदद करते हैं, जबकि बाकी दो पेनीबेसिलस टाइलोपी और बेसिलस डिकोलोरेटिओनिस क्रमशः फॉस्फेट और पोटाश को अधिक विलयशील बना कर काफी कम कीमतों पर पौधों के लिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे उपायों से प्रधानमंत्री का आह्वान फलीभूत हो सकता है, साथ ही इनसे कृषि उत्पादन पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं होगा।

तीन माह के अंदर हिंदी भवन का शिलान्यास होगा

रांचीः मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी प्रेमियों, साहित्यकार, रचनाकार, कवि को समर्पित हिंदी भवन का शिलान्यास तीन माह में होगा। देश भर से झारखण्ड आने वाले साहित्यकारों, रचनाकारों और कवियों को बातचीत, आयोजन व अन्य गतिविधियों के लिए एक उचित परिसर देना सरकार का उद्देश्य है। कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग अगले वर्ष से हिंदी दिवस का आयोजन संध्या बेला में मोरहाबादी मैदान में करे। जहां लोग कवि सम्मेलन का आनंद लें और युवा कवियों को सरकार एक मंच देने में सफल हो सके।उन्होंने कहा कि स्वभाषा के माध्यम से भारत विश्वगुरु बन सकता है। स्वभाषा विकास का परिचायक है। यह भारत के स्वाभिमानी भारत बनने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। कोई भी विकसित राष्ट्र के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण स्वभाषा है। मैं यह नहीं कहता कि अन्य भाषा का उपयोग न करें। आप उनका भी सम्मान करें।

प्लास्टिक के खिलाफ जनांदोलन ताकि बेहतर हो हमारा पर्यावरण

प्रहलाद सबनानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा है कि जब दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जनांदोलन की नींव भी रखेंगे।

एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के प्रयास को एक जनांदोलन का रूप देना होगा। इस दिशा में समाज भी सजग हो रहा है। कई व्यापारियों ने तो अपनी दुकानों में तख्ती लगा दी है, जिसमें लिखा है कि प्रिय ग्राहक, अपना थैला साथ लेकर आएं, ताकि एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म किया जा सके। इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में सभी देशवासी अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे पाएंगे। देश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों एवं प्रत्येक नागरिक से अनुरोध भी किया गया है कि प्लास्टिक कचरे के संग्रह के लिए उचित व्यवस्था की जाए। कॉरपोरेट सेक्टर से अपील की गई है कि जब ये सारा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो जाए, तो इसके उचित विघटन के लिए वे भी आगे आएं।प्लास्टिक, विशेष रूप से एकल उपयोग प्लास्टिक, देश के पर्यावरण, नागरिकों, पशु-पक्षियों, समुद्री जीवों, आदि के लिए कितना खतरनाक है, इस भयावह स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। दरअसल, प्लास्टिक आसानी से विघटित नहीं होता है एवं इसका स्वरूप लगभग हजार वर्षों तक बना रहता है। विश्व में प्लास्टिक का उपयोग इतना बढ़ता जा रहा है कि पिछले दस वर्षों के दौरान जितना प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। इन सभी प्लास्टिक उत्पादों में से 50 प्रतिशत प्लास्टिक उत्पाद केवल एक बार ही उपयोग कर फेंक दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इतना प्लास्टिक धरती एवं समुद्र में फेंका जाता है कि यदि ये पूरा प्लास्टिक एक कड़ी के रूप में जोड़ा जाए, तो इस कड़ी के माध्यम से भू-भाग के चार चक्कर लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में केवल पांच प्रतिशत प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है, शेष 95 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का रूप ले लेता है। पूरे विश्व में लगभग 50,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियां प्रतिवर्ष उपयोग में आती हैं। सामान्यतः प्लास्टिक कचरे को समुद्र में फेंक दिया जाता है, इससे समुद्र के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं समुद्री जीव इसका शिकार हो रहे हैं। प्रतिवर्ष समुद्र में 10 लाख समुद्री पक्षी एवं एक लाख समुद्री स्तनपायी जीवों की जीवनलीला प्लास्टिक पदार्थ खाने से समाप्त हो जाती है। भारत में तो कई पशु-पक्षी (गाय, भैंस आदि) प्लास्टिक के पदार्थों को खाकर अपनी जान गवां बैठते हैं। प्लास्टिक कचरे का भंडार हमारे देश के लिए भी एक गंभीर समस्या बन गया है। महानगरों, शहरों, एवं अब तो ग्रामीण इलाक़ों में भी प्लास्टिक कचरे के भंडार के पहाड़ आसानी से देखे जा सकते हैं। हम नागरिकों की जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है कि भविष्य में किस प्रकार हमारे जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित किया जाए। हमें केवल कुछ आदतें अपने आप में विकसित करनी होंगी। यथा, जब भी हम सब्जी एवं किराने का सामान आदि खरीदने जाएं, तो कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। रेलवे प्लेटफॉर्म एवं हवाई अड्डों पर भी अब चाय एवं कॉफी कुल्हड़ में परोसी जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब समय आ गया है कि देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराया जाए, ताकि न केवल मासूम पशु-पक्षियों की जान बचाई जा सके, बल्कि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके।

पेड़-पौधे जीवन एवं संस्कृति दोनों के लिए जरूरी: मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में विस्थापन प्रमुख समस्या रही है। विकास कार्यों के लिए लोगों की जमीन तो ली जाती रही है और उन्हें विस्थापित बनाकर छोड़ दिया जाता रहा। जमीन मालिक होते हुए वे विस्थापित कहलाते रहे, उन्हें जमीन के कागजात नहीं दिये गये। लेकिन हमारी सरकार का मानना है कि विकास कार्यों के लिए जमीन देनेवाला व्यक्ति ही असली मालिक है। उन्हें हम उजाड़ने से पहले बसाने का काम कर रहे हैं। उन्हें मालिक बनाया जा रहा है। विधानसभा की जमीन के विस्थापितों के लिए जो यह कालोनी बनायी गयी है, यह एक मिसाल है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने कुटे स्थित विस्थापन एवं पुनर्वास कालोनी में वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कही।

कॉलोनी का नाम स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नाम पर किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कालोनी का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी

ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नाम पर किया जायेगा। इस कालोनी को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव कालोनी के नाम से जाना जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कालोनी में सरकार ने वृक्षारोपण कर दिया है। अब आप सबों की यह जिम्मेवारी है कि इनकी देख-रेख करें। पेड़-पौधे जीवन और संस्कृति दोनों के लिए जरूरी हैं। इनका संरक्षण करना है। इसके साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। महिलाएं सखी मंडल बनायें, सरकार उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार के साथ जोड़ेगी मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि यहां की महिलाएं सखी मंडल बनायें। सरकार उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार के साथ जोड़ेगी। इस वर्ष नवंबर से राज्य की 40 हजार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा। ये सभी महिलाएं सखी मंडल से जुड़ी हुई हैं। इन्हें रेडी टू इट योजना से जोड़ा जा रहा है। अब ग्रामीण महिलाएं ही आंगनबाड़ी के लिए पौष्टिक आहार तैयार कर भेजेंगी। इससे राज्य के 500 करोड़ रुपये जो बाहर जाते थे, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहां थोड़े बहुत काम बाकी रह गये हैं। जनवरी के पहले उन्हें पूरा कर लिया जायेगा। 14 जनवरी के बाद यहां गृह प्रवेश कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि कालोनी में ही स्कील डेवलेपमेंट का कैंप लगाकर यहां की महिलाओं को हाउस कीपिंग, टेलरिंग व युवाओं को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिये जायेंगे। नये विधानसभा, सचिवालय भवन में इन्हें रोजगार मुहैया कराया जायेगा। ताकी ये घर पर रहते हुए ही काम कर सकें।

कार्यक्रम में हटिया विधायक श्री नवीन जायसवाल, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री इंदूशेखर चतुर्वेदी, भवन सचिव श्री सुनील कुमार, हेड ऑफ फोरेस्ट श्री संजय कुमार, पीसीसीएफ श्री शशि नंद कुलियार समेत अन्य अधिकारी व स्थानीय निवासी उपस्थित थे।

जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा से सीखे देश

भूजल के गिरते स्तर और बढ़ते जल संकट से पार पाने के मकसद से हरियाणा सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। सरकार ने धान की खेती छोड़ कर मक्का और अरहर बोने वाले किसानों के लिए दो हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने, पंद्रह सौ से अठारह सौ रुपए कीमत का मक्का और अरहर का बीज मुफ्त देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम की पूरी राशि सरकार की तरफ से देने और मक्का तथा अरहर की खरीद में मदद की योजना तैयार की है। इसके लिए किसानों को सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण करा कर बताना होगा कि वे पहले कितने एकड़ जमीन पर धान की खेती करते थे और अब कितने एकड़ भूमि पर अरहर और मक्का की खेती करने जा रहे हैं। पंजीकरण के साथ ही दो सौ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से रकम उनके खाते में डाल दी जाएगी। बाकी रकम भूमि सर्वेक्षण के बाद दी जाएगी। माना जा रहा है कि इससे काफी किसान धान की खेती छोड़ देंगे। इस तरह सिंचाई के लिए हो रहे अनावश्यक भूजल दोहन पर काबू पाया जा सकेगा।

पिछले काफी समय से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों में किसान समय पूर्व धान की फसल लगाते आ रहे हैं। मई के महीने से ही धान की रोपाई शुरू कर देते हैं। इस तरह वे एक ही खेत में दो बार धान की फसल लगा लेते हैं। उनका मानना है कि इस तरह उन्हें धान से अधिक कमाई हो जाती है। धान दरअसल, बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसल

है। इसकी सिंचाई में काफी पानी की जरूरत होती है। धान के खेत में हमेशा पानी बने रहना चाहिए। इस तरह जब गरमी के मौसम में धान की पैदावार ली जाती है, तो उसकी सिंचाई के लिए भूजल का जरूरत से ज्यादा दोहन करना पड़ता है। किसानों की समय पूर्व धान की फसल उगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकारें लगातार अपील करती रही हैं। कई बार उन्होंने कुछ कड़े कदम ड्ढाी उठाए। पंजाब सरकार ने एक बार ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ भारी जुर्माने तक का प्रावधान कर दिया था।

मगर समय पूर्व धान की फसल उगाने की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में धान की अच्छी किस्में पैदा होती हैं। वह चावल ऊंची कीमत पर बिकता है, इसलिए किसान इसकी फसल उगाना फायदेमंद मानते हैं। वे एक मौसम में धान की दो फसल लेना चाहते हैं। मगर हकीकत यह ड्ढाी है कि कोई भी फसल जब अपने तय मौसम के बजाय पहले या बाद में उगाई जाती है, तो वह उचित पैदावार नहीं दे पाती। उसमें रोगों के आक्रमण की आशंका भी अधिक रहती है। सिंचाई, खाद, कीटनाशक आदि का खर्च बढ़ जाता है। उस फसल पर उत्पादन लागत सही समय में उगाई जाने वाली फसल की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। फिर जिस तरह मानसून की अवधि और बरसात की मात्रा लगातार घट रही है, उसमें धान की सिंचाई के लिए किसानों को लगातार भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है, जो जल संकट का बड़ा कारण है। ऐसे में हरियाणा सरकार की पहल से इस दिशा में अच्छे परिणाम आ सकते हैं।

फोटो न्यूज

फोटोः संजय बोस

बूढे हाथों की नायाब कलाः जोन्हा फॉल के पास बांस से सुंदर फूल, कलाकृतियों को बनाने वाले कलाकार की है। फोटोग्राफर और फिल्मकार संजय बोस ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया ।

नीरज झा के फेसबुक वाल से

नयी शुरूवातः एशिया के सुपर मार्केट में प्लास्टिक के बजाय केले के पत्ते में पैकेजिंग

बच्चे और युवा पीढी के सजग होने से ही आगे पर्यावरण बचेगा। बेड़ो के रामकृष्ण विद्या निकेतन में बच्चों ने पर्यावरणीय समाचार पत्र ग्रीन रिवोल्ट में रूचि दिखायी और वहां के शिक्षकों ने भी इसके विषय वस्तु का सराहा।

अद्भूत कृतियों के रचयिता हैं देव शिल्पी विश्वकर्मा

हिन्दू धर्म में अलग अलग कार्यों की जिम्मेवारी अलग अलग देवी देवताओं के पास है। जैसे धन के लिये लक्ष्मी, विद्या और कला के लिये सरस्वती, वायू के लिये पवन देव, जल के लिये वरूणदेव। वैसे ही इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी के देवता विश्वकर्मा हैं। हमारे पुराणों और जनश्रुतियों में जितनी भी अद्भूत कृतियां, उपकरण हैं वह विश्वकर्मा की ही बनाई हुयी हैं। इसी कारण से इन्हें देवशिल्पी भी कहा गया है। आज भी जब जब कोई मैकेनिक अपने काम में व्यवधान या मुश्किल देखता है तो वह भगवान विश्वकर्मा को ही याद करता है और उसके मुख से जय बाबा विश्वकर्मा निकलता है।

हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। और तकरीबन सभी बड़े मशीनरी वाले प्रतिष्ठानों से लेकर अखबार और बाइक रिपेयरिंग दूकान तक बंद रहते हैं। इस दिन तकनीशियन, मैकेनिक सभी देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। हिन्दू पूजन में कई व्यावहारिक और वैज्ञानिक बातें छुपी रहती है। विश्वकर्मा पूजन में भी यह बात जुड़ी हुयी है कि इसी बहाने मशीनों से लेकर सभी प्रकार के उपकरणों और टूल्स औजार की भी सर्विसिंग एवं साफ सफाई हो जाती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन सभी लोग जो मशीनों औजरो आदि से अपना काम करते है। वे सुबह सबसे पहले अपने कल कारखानों की सफाई के साथ अपने मशीनों और औजारों की भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई किया जाता है फिर इसके बाद विश्वकर्मा भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन कल कारखानो में बड़े ही हर्सोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। कई जगहों पर भी विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थपित की जाती है।

विश्वकर्मा सिर्फ देवशिल्पी ही नहीं थे, बल्कि कई ऐसी अद्भूत कृतियों के रचयिता भी थे जिसके कारण बहुत सारे प्रसंग और युद्ध तक हुये। स्वर्ग, हस्तिनापुर, पुष्पक विमान, सोने की लंका से लेकर विष्णु के सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा ने ही बनाये थे। पुराणों के अनुसार सृस्टि की रचना आदिदेव ब्रह्मा जी को माना जाता है। विश्वकर्मा जी की सहायता से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इसी कारण इन्हें देवताओ का इंजीनियर भी कहा जाता है। इन्हीं अद्भूत और रोचक कृतियों के निर्माण के कारण इन्हें देवशिल्पी कहा गया।

सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अलग अलग निर्माण

चार युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। कालक्रम में देखें तो सबसे पहले सत्ययुग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारका का और कलियुग के आरम्भ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इन्द्रप्रस्थ का निर्माण किया।कहते हैं विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में स्थित विशाल मूर्तियों (कृष्ण, सुभद्रा और बलराम) का निर्माण किया।

देवताओं में भी पूजनीय

विश्वकर्मा के आविष्कारों और इंजीनियरिंग के गुणों के कारण ही देवताओं में भी इनकी खास प्रतिष्ठा थी। हम अपने प्राचीन ग्रंथो उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पायेगें कि आदि काल से ही विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण न मात्र मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित है। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण को हम देखें तो इन्द्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पाण्डवपुरी, सुदामापुरी, शिवमण्डलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होनेवाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुण्डल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशुल और यमराज का कालदण्ड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। विश्वकर्मा के विशेष प्रतिष्ठित होने का एक कारण आज के संदर्भ में भी हम देखें तो समझ सकते हैं, वो है आवश्कताओं और धन वैभव के लिये वर्चस्व के लिये उपयोगी साधनों का आविष्कारक होना ।

कौन थे देवशिल्पी विश्वकर्मा?

हिन्दू धर्म शास्त्रो के अनुसार सबसे ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के सातवे संतान जिनका नाम वास्तु था। विश्वकर्मा जी वास्तु के पुत्र थे जो अपने माता-पिता की भांति महान शिल्पकार हुए । एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना जो ब्रह्मविद्या जानने वाली थी वह अष्टम वसु महर्षि प्रभास की पत्नी बनी और उससे सम्पुर्ण शिल्प विद्या के ज्ञाता प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। स्वर्ग ,लंका भगवान कृष्ण जी की द्वारिका और पांडवो की राजधानी हस्तिनापुर इन सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा की गयी है जो की वास्तु कला की अद्भुत मिशाल है। स्वर्ग निर्माण के बाद वहां की अद्भूत वस्तुओं का भी इन्होंने निमर्णण कियाविश्वकर्मा को औजारों का देवता भी कहा जाता है। यही कारण है कि इनके हाथों में आरी, हथौड़ी जैसे औजार धारण किये हुये दिखाया जाता है।

विश्वकर्मा के पुत्र एवं वंशज

कन्दपुराण के नागर खण्ड में भगवान विश्वकर्मा के वशंजों की चर्चा की गई है । उनके पांच मुख है उनके नाम है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ ।
ऋषि मनु विश्वकर्मा - ये लोहे के का काम करते हैं। इनके वशंज लोहकार के रुप मे जानें जाते है ।
सनातन ऋषि मय - ये सनातन गोत्र के कहे जाते है । इनके वशंज काष्टकार के रुप में जाने जाते है।
अहभून ऋषि त्वष्ठा - इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते है ।
प्रयत्न ऋषि शिल्पी - इनका दूसरा नाम शिल्पी है इनके वशंज शिल्पकला के अधिष्ठाता है इन्हें मुर्तिकार भी कहते हैं ।
देवज्ञ ऋषि - इनके वशंज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं । ये रजत, स्वर्ण धातु के शिल्पकर्म करते है, ।

बीट का जूस स्वास्थ्य के लिये है लाजवाब

कई पोषक तत्वों के गुण वाला बीट का जूस एक ऐसी चीज है जो कई मायनों में शरीर के लिए एक आदर्श टॉनिक है, एक ग्लास ताजा तैयार बीट यानि लाल चुकंदर का रस आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। इसमें सभी आवश्यक विटामिन और खनिज सबसे शोषक और पौष्टिक रूप में होते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर नाश्ते से पहले सुबह के शुरुआती घंटों में इसका सेवन किया जाता है, तो यह बहुत लाभप्रद होता है। चुकंदर के जूस में मौजूद वायलेटॉक्सिन, एक एंटीऑक्सिडेंट, और बीटानि, एक अमीनो एसिड जैसे घटक कैंसर को ठीक करने वाले गुण होते हैं। ये रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं, जो कि कैंसर के लिए एक संभावित खतरा होते हैं। यह पाचन को बढ़ाता है, चुकंदर का जूस आंखों के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है क्योंकि इनमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और यह आंखों की समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और इसे सामान्य के करीब रखने में मदद करता है। डायबिटीज वाले सभी लोगों के लिए यह एक वरदान है। यह रक्त में शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि की संभावना को रोकता है।

कुछ कहता है ये स्टिकर

नरेन्द्र कुमार

अक्सर हम फलों पर सिटकर लगादेखते हैं। मगर क्यों लगाया गया यह पता नहीं होता। आपने कभी देखा होगा कि जब भी फल खरीदने जाते हैं तो उन पर कई बार स्टीकर लगे हुए देखते हैं। खासकर ये सेब पर लगे होते हैं। कई बार हम ये कयास लगाते हैं कि सप्लायर ने या पैकिंग करने वाले ने अपनी कंपनी का स्टिकर लगाया होगा? दरअसल, फलों पर लगे स्टिकर्स का अपना विशेष महत्व होता है। इन स्टिकर्स पर एक कोड दिया होता है जिसे PLU (प्राइस लुक-अप) कहा जाता है। ये अलग-अलग प्रकार के होते हैं, और इनका मतलब भी अलग होता है । अगर इन स्टीकर्स पर लगे कोड को हम पहचान लें तो फलों के बारे में कई तरह की जानकारियां ले सकते हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन-से फल हमें लेने हैं और कौन-से नहीं। आइये हम स्टिकर के कोड से जानें कि फल किस तरह का है?

फलों पर लगे स्टिकर के अंक बताते हैं, फल किस तरह से उगाया गया है

- जिन फलों या सब्जियों पर लगे स्टिकर्स में 4 डिजिट वाला कोड होता है वह यह दर्शाता है कि इन फलो को उगाते समय ट्रेडिशनल किटनाशकों या केमिकल्स का यूज किया गया है।
- जिन फलो पर 4 डिजिट वाले अंक (उदा। 4017) होते हैं उसका मतलब हैं कि इन फलो को उगाने के लिए भारी मात्रा में किटकनाशको का प्रयोग किया गया हैं। मतलब जिन फलों पर 4 डिजिट वाले नम्बर हैं वो फल नहीं खरीदने चाहिए।
- जिन फलों पर 5 डिजिट वाले नम्बर है और वो 8 अंक से शरू होता है (जैसे 80412) तो इसका मतलब हैं कि इसे जैविक रूप से उगाया गया हैं। लेकिन इसमें अनुवांशिक संशोधन किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसे जैविक रूप से उगाया गया है। इसे जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई किया जाता है।।।।।।।ये 4 डिजिट वाले अंक से अच्छे होते हैं।
- किसी फल या सब्जी पर लगे स्टीकर पर 5 डिजिट का कोड है और यह 9 नंबर से शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि इसे जैविक रूप से उगाया गया है। लेकिन इसे जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई नही किया जा सकता।
- जिन फलों पर 5 डिजिट वाले नम्बर है और वो 9 अंक से शुरू होता हैं (जैसे94285) तो इसका मतलब हैं कि इसे जैविक रूप से उगाया गया हैं। ये फल सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं।

सूखे खेत में भी उपजने वाला और अपने गुणों के कारण सुगर फ्री चावल के तौर पर कोदो पहचाना जाता है

औषधीय गुणों वाला अनाज है कोदो

कोदोः एक उपेक्षित अनाज
शुगर फ्री चावल के तौर पर पहचाने जाने वाले कोदो को अब लोग भूलने लगे हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शुमार इस अनाज को बचाने और लोकप्रिय बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं।

शहरों की चकाचौंध और तमाम तरह के अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के संग हमारी दिनचर्या ऐसी घुलमिल गई है कि हमारे पास पौष्टिक खाद्य पदार्थों के विकल्प सीमित हो चले हैं। ऐसा ही एक अनाज है कोदो, जिसे अंग्रेजी में कोदो मिलेट या काउ ग्रास के नाम से जाना जाता है। कोदो के दानों को चावल के रूप में खाया जाता है और स्थानीय बोली में भगर के चावल के नाम पर इसे उपवास में भी खाया जाता है। कोदो का वानस्पतिक नाम पास्पलम स्कोर्बीकुलातम है और यह भारत के अलावा मुख्य रूप से फिलिपींस, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका में उगाया जाता है।

दक्कन के पठारी क्षेत्र को छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों में इसे बहुत ही छोटे रकबे में उगाया जाता है। इसकी फसल सूखारोधी होती है और ऐसी मिट्टी में भी आसानी से उगाई जा सकती है, जिसमे अन्य कोई फसल उगाना संभव नहीं है।

कोदो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में उगाया जाने वाला अनाज है। एक अनुमान के मुताबिक 3,000 साल पहले इसे भारत लाया गया। दक्षिणी भारत में, इसे कोद्रा कहा जाता है और साल में एक बार उगाया जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में एक बारहमासी फसल के रूप में उगता है और वहां इसे अकाल भोजन के रूप में जाना जाता है। अक्सर यह धान के खेतों में घास के समान उग जाता है।

दक्षिणी संयुक्त राज्य और हवाई में इसे एक हानिकारक घास के तौर पर जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह उपज जहां पक्षियों को खिलाने के काम आती है, वहीं दक्षिण अफ्रीका में इसके बीज लगाकर कोदो की खेती शुरू की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोदो-कुटकी की बहुत मांग है। शुगर फ्री चावल के नाम पर इसे फाइव स्टार होटलों में भी परोसा जा रहा है।

कोदो आदिवासियों का एक मुख्य भोजन रहा है और इससे जुड़े कई मिथक भी सुनने को मिलते हैं। वेरियर अल्विन की किताब जनजातीय मिथकः उड़िया आदिवासियों की कहानियां में एक कहानी मेघ गर्जना शीर्षक से प्रकाशित है। इस कहानी का सार कुछ इस प्रकार है- जब मनुष्य पैदा हुए तो महाप्रभु ने आकाश से पृथ्वी तक सड़क बना दी और मनुष्य उस पर चलकर आया-जाया करते थे। जब आबादी बढ़ी तब महाप्रभु ने मनुष्य समाज को जातियों में विभाजित कर दिया, उन सबको बसने के लिए स्थान दे दिया और आकाश-पृथ्वी वाले मार्ग को बन्द कर दिया। एक बार महाप्रभु मनुष्यों से मिलने आए तब उन लोगों ने महाप्रभु से पूछा, ''हमें किस महीने में धान और कोदो बोना चाहिए? ''वर्षा ऋतु आरंभ होने के पूर्व वाले महीने में मैं तुम्हें सूचना भेजूंगा और मेरे चपरासी भी आकाश से आकर तुम्हें बताएंगे और तुम्हें उनकी गर्जना भी सुनाई पड़ेगीं'', महाप्रभु ने उत्तर दिया। इसके बाद मनुष्य चपरासियों की घोषणा की प्रतीक्षा करने लगे। गर्जना के साथ ही उन्होंने अपने खेतों की बुआई कर ली और जब वर्षा ऋतु समाप्त होने को थी, तब भी चपरासियों ने गर्जना के जरिए उन्हें आगाह कर दिया कि वर्षा अब जाने वाली है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कोदो सदियों से जनजातीय समाज के लिए भोजन के रूप में कितना महत्त्व रखता है। विलुप्त हो रहे कोदो को बचाने के लिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो कृषि विभाग कई तरह की योजनाएं चला रहा है। कृषि अनुसंधान केन्द्र, रीवा के वैज्ञानिकों ने कोदो की नई किस्म तैयार की है, जिसे जेके-49 नाम दिया गया है। गौरतलब है कि कोदो औषधीय महत्व की फसल है। इसे शुगर फ्री चावल के नाम से ही पहचान मिली है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त आहार है। कम पानी में तैयार होने वाली फसल से किसान को अच्छा लाभ मिलने की बात वैज्ञानिक कह रहे हैं।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

सन कम्युनिकेशन द्वारा अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2 टीवीएस गली रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित एवं मैसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित। प्रकाशक सह कार्यकारी संपादक : मनोरंजन सिंह, संपादकः मनोज कुमार शर्मा*
आर.एन.आइ. नंबर : JHAHIN00962. email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन ही होंगे।